No. Fin-G-A(3)-1/2018
Government of Himachal Pradesh
Finance (Budget) Department.

From

Jai Ram Thakur,
Chief Minister,
Himachal Pradesh.

To

The Hon'ble Speaker,
H.P. Vidhan Sabha, Shimla-04

Dated Shimla-171002, the 10/08/2022

Subject: Notice of motion for leave to introduce the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2022 (Bill No. 14 of 2022).

Sir,

I intend to give a notice of motion for leave to introduce the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2022 (Bill No. 14 of 2022) before the State Legislative Assembly in the present Session. It is, therefore, requested that this may please be included in the list of the Assembly Business in relaxation of rules.

Three authenticated copies of the said Bill both in Hindi and English are sent herewith.

Yours faithfully,

(Jai Ram Thakur)
Chief Minister, Himachal Pradesh.

2022 का विधेयक संख्यांक 14

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2022

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 5 का संशोधन।

2022 का विधेयक संख्यांक 14

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 14) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

धारा 5 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के परन्तुक के अन्त में ";" चिन्ह के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः

"परन्तु यह और कि वित्तीय वर्ष 2020—21 में राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत स्तर से अधिक हो सकेगा किन्तु यह प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम वर्ष 2005 में अधिनियमित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण करों की वास्तविक प्राप्तियों में कमी आई है, जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय करों में राज्यों के भाग (हिस्से) की प्राप्तियां भी प्रभावित हुई हैं। माल और सेवा कर प्रतिकर में कमी के कारण, केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति प्रदान की है।

अतः विकास की गति, जिस पर कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने आंशिक अतिरिक्त उधार लिया है। इसलिए, हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 (2005 का राज्य अधिनियम संख्यांक 14) में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जय राम ठाकुर)
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख : ...., 2022

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध, अधिनियमित होने पर, विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे। राज्य सरकार को वर्ष 2020–21 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तीन प्रतिशत के राजकोषीय घाटे की वर्तमान सीमा जो कि 2005 के अधिनियम संख्यांक 14 में निर्धारित है, से 2 प्रतिशत अधिक उधार लेने की अनुमति राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति तथा विकास की गति को बनाए रखने हेतु प्रदान की गई है। राज्य की राजकोषीय स्थिति तदनुसार प्रभावित हुई है।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2022

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 14) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

(जय राम ठाकुर)
मुख्य मन्त्री।

(राजीव भारद्वाज)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख : ...., 2022

f

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 14) के उपबन्धों के उद्धरण

धारा :

5. राजकोषीय प्रबन्ध लक्ष्य.—(1) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार–

(i) वित्तीय वर्ष 2011–12 तक राजस्व घाटा समाप्त करेगी और तत्पश्चात् राजस्व अधिशेष बनाए रखेगी;

(ii) राजकोषीय घाटे को, वित्तीय वर्ष 2010–11 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत तक या इससे कम करेगी, वित्तीय वर्ष 2011–12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक या इससे कम करेगी और तत्पश्चात् राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के स्तर तक या इससे कम पर बनाए रखेगी:

परन्तु वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 और 2019–20 में राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत स्तर से अधिक हो सकेगा किन्तु यह प्राक्कलित राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

(iii) परादेय ऋण को वित्तीय वर्षों 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14 और 2014–15 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः 49.7 प्रतिशत, 47.0 प्रतिशत, 44.4 प्रतिशत, 42. 1 प्रतिशत और 40.1 प्रतिशत, तक कम करेगी; और

(iv) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति, जिसके लिए वित्तीय लेखों के अनुसार वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हैं, के चालीस प्रतिशत से कम के दीर्घकालिक ऋण पर परादेय जोखिम भारित प्रत्याभूतियां बनाए रखेगी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से या, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा घोषित करने के कारण, राज्य सरकार के वित्त पोषण पर अप्रत्याशित मांगों की दशा में, उपधारा (1) के खण्ड (i), (ii) और (iii) के विभिन्न मानदण्डों के अन्तर्गत लक्ष्यों में बढ़ौतरी हो सकेगी:

परन्तु इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट आधार या आधारों के बारे में विवरण, ऐसे घाटे की रकम के उपरोक्त लक्ष्यों से अधिक होने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 14 OF 2022

THE HIMACHAL PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2022

(As Introduced in the Legislative Assembly)

THE HIMACHAL PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2022

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title.
2. Amendment of section 5.

Bill No. 14 of 2022

THE HIMACHAL PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2022

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (Act No. 14 of 2005).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2022.

Amendment of section 5.

2. In section 5 of the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, in sub section (1), in clause (ii), at the end of the proviso, for the sign ";" the sign ":" shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that the fiscal deficit may exceed the level of 3 per cent but shall not exceed 4 per cent of the estimated Gross State Domestic Product in the Financial Year 2020-21;".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act was enacted in the year 2005. The actual receipts of taxes declined during 2020-21 because of COVID-19 pandemic due to which receipts of share of States in Central taxes also got affected. Due to decline in Goods and Services Tax Compensation, the Central Government has allowed additional borrowing of 2 per cent of Gross State Domestic Product during the financial year 2020-21.

Thus, in order to maintain the pace of development which has been affected by COVID-19 pandemic, the State Government has availed partial additional borrowing. Therefore, it has become necessary to amend the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (State Act No. 14 of 2005).

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAI RAM THAKUR)
Chief Minister.

SHIMLA :

THE , 2022

FINANCIAL MEMORANDUM

Provisions of the Bill, when enacted, shall be enforced through the existing Government machinery. The State Government has been allowed to borrow upto 2 per cent more for the year 2020-21 than the present limit of fiscal deficit of 3 per cent of Gross State Domestic Product prescribed in the Act No. 14 of 2005 to compensate for loss of revenue of State and to maintain the pace of development. The fiscal position of the State has been impacted accordingly.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

THE HIMACHAL PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (Act No. 14 of 2005).

(JAI RAM THAKUR)
Chief Minister.

(RAJEEV BHARDWAJ)
Principal Secretary (Law).

SHIMLA :

THE , 2022

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT ACT, 2005 (ACT NO. 14 OF 2005) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

Section:

5. Fiscal management targets.—(1) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the State Government shall—

(i) eliminate revenue deficit by financial year 2011-12 and maintain revenue surplus thereafter;

(ii) reduce fiscal deficit to 3.5 per cent or less of Gross State Domestic Product by financial year 2010-11, 3 per cent or less of Gross State Domestic Product by financial year 2011-12 and maintain fiscal deficit at the level of 3 per cent or less of Gross State Domestic Product thereafter:

Provided that the fiscal deficit may exceed the level of 3 percent but shall not exceed 5 percent of the estimated Gross State Domestic Product in the Financial Years 2012-13, 2013-14, 2014-15 and 2019-20;

(iii) reduce outstanding debt to 49.7 per cent, 47.0 per cent, 44.4 per cent, 42.1 per cent and 40.1 per cent of Gross State Domestic Product by the financial years 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 and 2014-15 respectively; and

(iv) maintain outstanding risk weighted guarantees on long term debt below forty per cent of total revenue receipt in the preceding financial year for which actual are available as per finance accounts.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the targets under different parameters of clauses (i), (ii) and (iii) of sub-section (1), may be exceeded in the case of unforeseen demands on the finance of the State Government due to reasons of national security or natural calamity declared by the State Government or the Central Government, as the case may be:

Provided that a statement in respect of the ground or grounds specified under this sub-section shall be placed before the Legislative Assembly, as soon as may be, after such deficit amount exceeds the aforesaid targets.

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला—791—जुड0 / 2022—9—8—2022—175 प्रतियां।